गरियाबंद पुलिस प्रशासन के बेबुनियादी और झूठे प्रचार को ठोकर मारो !

प्रिय जनता

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनता पर जारी युध्द आपरेशन ग्रीनहंट के तहत माओवादियों को खत्म करने का नाकाम प्रायस करते पीछले दिनों गरियाबंद पुलिस ने अभियान चलाया और हमारे एरिया में दुश्प्रचार युध्द के तहत पर्चे फैंके. गरियाबंद पुलिस के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद ही नहीं झूठे भी हैं.

गुडसा उसेंडी का सच

पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर आरोप जनता व पार्टी के प्रति गद्दारी करने वाले गुडसा उसेंडी के हवाले से लगाए हैं. गुडसा उसेंडी के हमारी पार्टी के साथ कोई सैध्दांतिक मतभेद नहीं थे. न ही उसने कभी अपने अंतरविरोधों को पार्टी कमेटियों के सामने रखा था. उसने जीरमघाटी हमले, स्कूलों को गिराये जाने, 'निर्दोषों' को मारे जाने, महिलाओं के शोषण के उपर कई बार शासकों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का खंडन किया था. लेकिन आज वह वही भाषा बोल रहा है जो आंध्र प्रदेश का विशेष खुफिया विभाग यानि एपीएसआईबी बुलवा रही है. वह उनके हाथों बिक गया है. दरअसल गुडसा उसेंडी का नैतिक पतन हो चुका था. जिस महिला को लेकर सरेंडर हुआ वह उसकी पत्नि नहीं है. उस महिला से कामरेड उसके अवैध संबंध थे, उसका नाम संतोषी मरकाम है. सब जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचारों करने वालों पर माओवादी पार्टी कड़ी कार्रवाई करती है. गुडसा उसेंडी की गलती बाहार आ गयी थी. इसलिए वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से आंदोलन से ही भाग खड़ा हुआ ताकि बहार आराम और ऐश परस्ती की जिंदगी जी सके. अब वह अपनी गलती को छुपाने के लिए माओवादी पार्टी झूठे आरोप लगा रहा है. और उससे भी बड़ी बेशर्मी गरियाबंद पुलिस कर रही है - जो व्यक्ति अपनी पत्नि को छोड़कर दूसरी महिला को भगा कर ले गया, अवैध संबंध रख कर अनैतिक कार्य किया ऐसे पतीत व्यक्ति को आदर्श के रुप में पेश कर रही है. वह जनता व अन्य कैडर को भी वैसा ही पतीत व महिला विरोधी व्यक्ति बनने की शिक्षा दे रही है.

पहली झूठ - माओवादी महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं !

सच - हम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन भी मानते हैं कि माओवादी आंदोलन में महिलाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं. माओवादियों में 47 प्रतिशत तक महिलाएं हैं, न केवल नीचले कमांडर स्तर पर बल्कि उपरी कमेटियों में भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी है. अगर हम महिलाओं का शोषण करते तो क्यों इतनी संख्या में महिलाएं पार्टी में भर्ती होती! सच्चाई यह है कि पुलिस व अर्ध सैनिक बलों ने सैकड़ों से ज्यादा महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ में, दर्जनों महिलाओं के साथ ओड़िशा के बलांगिर, मलकनगिरी, कोरापुट जिलों में और सैकड़ों महिलाओं के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों व कश्मीर में सामूहिक बलात्कार किये हैं. कुंबिंग ऑपरेशनों के दौरान पुलिस व अर्ध सैनिक बल गांव की महिलाओं के साथ सरेआम छेड़खानी करते हैं. जंगलवार कॉलेज कांकेर के गांव पात्थरी की महिलाएं उसे वहां से उठाने के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं. पुलिस के रंगरुट गांव में घुसकर महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं. शौच के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं को उठाकर उनसे बलात्कार करते हैं. गांव की महिलाओं का अकले निकलना मुश्किल हो गया है. ऐसा ही हाल सभी पुलिस थानों व कैंपों के गांव का है. उस पुलिस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिस ने एक सरकारी शिक्षिका सोनी सोडी के साथ हिरासत में एसपी के नेतृत्व में बलात्कार किया और उतना ही नहीं मानवता को शर्मसार करते हुए, बर्बर व पाश्विक तरीके से उसकी योनि में पत्थर तक डाल दिये. इसकी रिपोर्ट कलकता के एक हस्पताल में जांच के बाद जारी की. ऐसा कुकृत्य करने वाले अंकित गर्ग को राष्ट्रपति ने पदक से नवाजा, पुलिस ने पदोन्नति दी! अब वही पुलिस नैतिक रुप से पतीत हो चुके गुडसा उसेंडी को आदर्श के तौर पर पेश कर रही है. तो पहचानीये माहिलाओं का शोषण कौन करते हैं माओवादी या पुलिस ?

दूसरा झूठ - माओवाद से विकास के रास्ते बंद हो रहे हैं, बिजली, शिक्षा और ईलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है! सड़कें नहीं बन रही हैं!

सच - विकास के विरोधी माओवादी नहीं हैं, दरअसल सरकार और पुलिस बड़े पूंजीपतियों, जमींदारों और विदेशी कंपनियों के फायदे को ही विकास समझती है. छत्तीसगढ़ में हजारों किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है. प्रति एक किलोमीटर सड़क के लिए डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया गया है. और सरकार के विधायक खुद सच्चाई उगल रहे हैं कि बस्तर की 32 लाख की आबादी के लिए 100 एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है! राज्य में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां शिक्षकों की संख्या पूरी हो. बिजली का निजीकरण कर दिया गया है. राज्य की बिजली को पूंजीपतियों को कौड़ियों के मोल दिया जाता है, जबकि किसानों को बिजली की आपूर्ति मात्र छः घंटे, वह भी लगातार नहीं की जाती जिस कारण किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं. प्रति दिन एनएमडीसी 85 करोड़ रुपये बैलाडिला खदान से कमाती है लेकिन साल में एक दिन की कमाई भी जनता के विकास के लिए नहीं खर्च करती. ऐसा ही हाल अन्य कंपनियों का है! तो क्या माओवादी विकास के विरोधी हैं? आदिवासी इलाकों को बरसों से लूट रही सरकार को माओवादी पार्टी के आंदोलन के बाद ही 'विकास' की बात याद आई. उससे पहले सरकार कहां थी? क्यों पुलिस-फोर्स पर हजारों करोड़ रुपाये खर्च किये जा रहे हैं और क्यों राज्य के 60 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. क्यों कर साल डेढ हजार के आसपास किसान आत्महत्या कर जाते हैं? किसके विकास के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि निजी कंपनियों को दे दी गयी और किसके विकास के लिए सितानदी, उदंती से लेकर आमामोरा तक आदिवासी व किसानों को उजाड़कर टाईगर परियोजना पर अमल किया जा रहा है?

तीसरी झूठ - ग्रामीणों द्वारा माओवादी नक्सलियों का विरोध

सच - यह एक और सफेद झूठ है. पुलिस ने इसे सच्च जैसा समझाने के लिए दो फोटो भी छाप दिये हैं. पुलिस का कहना है कि ओड़िशा के सोनाबेड़ा और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के ठुठीअंबा गांव के लोगों ने माओवादियों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं. गांव सोनाबेड़ा में नुआपाड़ा के एसपी उमाशंकर दास ने मुखबिरों का नेटवर्क बनाया था. उसने कुछ को तो गैरकानूनी तरीके से एके-47 जैसे घातक हथियार भी दिये थे ताकि माओवादी नेताओं को मारा जा सके. जनता में इसका पर्दाफाश हुआ. दो मुखबिरों को पकड़कर माओवादी पार्टी ने एक का सफाया कर दिया जबकि एक को जनता के कहने पर माफ कर दिया था. अपने मुखबिर नेटवर्क को बचाने के लिए मुखबिरों के जरिये एसपी ने जनता को भड़काया लेकिन जल्द ही जनता को इस साजिश का पता चल गया. पुलिस ने इसको आधार बनाकर जबरन उस गांव में कैंप डाल दिया. यही पुलिस का लक्ष्य भी था. पुलिस मुखबिरों का जीते जी सुचना जमा करवाकर फायदा उठाती है, उनके खत्म होने पर 'आम जानता को नक्सलियों ने मारा' कहकर दुश्प्रचार कर फायदा उठाती है. इस प्रकार पुलिस को दोनों तरीके से फायदा है, जबकि बलि का बकरा बनते हैं मुखबिर!

ठुठीअंबा गांव की जनता ने माओवादियों के खिलाफ नहीं पुलिस के खिलाफ ही हथियार उठाये हैं. इसकी सच्चाई समझीये - माओवादी पार्टी से कुछ भागे और सरेंडर कर चुके नकली नक्सली - पीएलएफआई, जेपीसी, टीपीसी आदि टोलियां बनाए. अब वह लोग पुलिस के साथ मिलकर जनता, पूंजीपतियों, दुकानदारों आदि से बंदूक दिखाकर पैसे वसूलते हैं, इसमें थाने दार से लेकर एसपी तक का हिस्सा होता है. इस साठगांठ से जनता परेशान हो चुकी है. नकली नक्सलवादियों की आड़ में हमारी पार्टी के खिलाफ दुश्प्रचार किया जा रह है जबकि वह लोग पुलिस के ही लोग होते हैं. इसलिए जनता ने भाकपा (माओवादी) के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस के टटटुओं के खिलाफ हथियार उठाये हैं. हम जनता की इस पहल का समर्थन करते हैं. और अपील करते हैं कि पुलिस व नकली नक्सलियों के गठजोड़ का पर्दाफाश कर उन्हें मार भागएं.

प्रिय जनता, किसान-मजदूरों, छात्र-नौजवानों, माताओ-बहनों, दुकानदार-व्यापारियों, कर्मचारी-बुध्दिजीवियो आप सबसे हमारी पार्टी की अपील है कि गरियाबंद पुलिस के इस झूठे प्रचार को सिरे से खारिज कर ठोकर मार दो. माओवादी पार्टी के खिलाफ पुलिस की साजिशों का पर्दाफाश करें, पुलिस की अनैतिक असामाजिक शिक्षा की भर्त्सना करे!

मैनपुर-नुआपाड़ा डिवीजनल कमेटी

भाकपा (माओवादी)

17 फरवरी 2014